(g) Regulation of Forward Contracts in the trade in major commodities.

(h) Delegation of powers to State Governments to control the distribution and prices of commodities declared essential under the Essential Commodities Act, 1955.

Annexure—II

(Rs. in Crores

Security	*Outstanding as on*		
	March 14, 1968	March 14, 1969	March 13 1970
Foodgrains	21.0	40.0	55.0
(a) Rice and Wheat Flour Mills.	6.9	10.9	1.58
(b) Others	14.1	29.1	39.2

*Based on Security-wise classification of advances and exclude advances against foodgrains to State Governments and Food Corporation of India.

Demands of all India Telegraph Engineering Employees Union (Class III)

5067. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(b) whether the Divisional Branch, Darbhanga (Bihar) of the All India Telegraph Engineering Employees Union (Class III) has submitted demands for immediate stoppage of rotational transfers for settling of personal claims, repatriation and for welfare of the staff ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes.

(b) Rotational transfers have been ordered in May, 1970 in accordance with orders in force. Due consideration has been given to individual case of hardship. Step are being taken to settle personal claims of the staff. Repatriation of staff from Darbhanga to Muzaffarpur Division has been arranged in a phased manner as and when vacancies are available.

बीड़ी उद्योग के श्रमिकों की मजूरी

5068. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी पुनर्निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन कब हुआ था और उन प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ; जिन्होंने इसमें भाग लिया तथा उसके निष्कर्षों और सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तिथि को ऐसी बैठक बुलाने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन का मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है । विभिन्न राज्यों में निर्धारित मजदूरी-दरों की विषमताएं कम करने के प्रश्न पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बुलाई गई न्यूनतम मजदूरी केन्द्रीय सलाहकार बोर्डों, सम्बंधित राज्यों के श्रम मंत्रियों, आदि की विभिन्न बैठकों में, विचार-विमर्श किया गया है ।